

साढ़े तीन सौ क्षतिग्रस्त मकानों का किया सर्वे

हरिद्वार, एजेंसी। न्याय पंचायत के लालडांग, स्मूलपुर, मोटीबेरी, गैंडीखाता ग्राम पंचायत में बोक्सा जनजाति शक्तिग्रस्त मकानों का सर्वे किया गया। जिनमें साढ़े तीन सौ क्षतिग्रस्त हो चुके मकानों का सर्वे कर सकते हैं। ब्लॉक प्रशासन को दी जा चुकी है। लालडांग न्याय पंचायत के मोटीबेरी छिड़ियानवाला, मोहल्लापुरी, नई बस्ती, सांचेर गांव, बड़ा स्मूलपुर, गैंडीखाता इडनार, नया गांव चमरिया आदि गांव में बोक्सा जनजाति के लगभग बारह सौ परिवार मूल रूप से निवास करते हैं। जिन्हें वर्षों पूर्व जनजाति योजना के तहत आवास बनाकर दिए गए थे जो जरूर हो गए थे। इनमें बस्ताओं के मौसम में कभी भी बड़ा हास्त होने की आशंका है। इसी को लेकर ब्लॉक बहादराबाद प्रशासन की ओर से बोक्सा जनजाति के शक्तिग्रस्त मकान का सर्वे किया गया। स्मूलपुर मोटीबेरी ग्राम पंचायत के स्मूलपुर, स्मूलपुर छिड़ियानवाला, मोटीबेरी आदि गांव से 354 क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे किया गया। गैंडीखाता ग्राम पंचायत के इंदिरा नगर व गैंडीखाता में 163 परिवारों क्षतिग्रस्त मकानों के सर्वे किया गया। लालडांग ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान दिनेश कर्णवाल ने बताया कि मोहल्लापुरी में 118, सांचेर गांव में 17, नई बस्ती 10, जसपुर चमरिया में और ब तवस्ता नगरागांव में लगभग 40 परिवारों का सर्वे किया गया।

रक्षाबंधन पर मायके जाने से रोका तो रेलवे ट्रैक पर बैठी महिला

रुड़की, एजेंसी। रक्षाबंधन पर पती को मायके जाने से रोकने पर वो आत्महत्या करने के लिए रेलवे लाइन पर बैठ गई। लोगों ने किसी तरह महिला को समझाकर रोका तो लाइन पर हाया। आरोपी जीवांगी ने अपने गांव को समझाकर परियों के सुरुपति कर दिया है। कोतवाली क्षेत्र के अकोडा खुद गांव निवासी एक महिला का मायका ज्वालापुर में है। बताया जा रहा है कि महिला बुहस्तिवार को रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बाधे के जाने की तैयारी कर रही थी। इस बीच पति ने उसे मायके जाने से मना कर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े एक हजार से अधिक स्थानीय लोगों को देहरादून निदेशालय से अनुमति दी गई।

भीमताल और नौकुचियाताल आने वाले सैलानियों के लिए अच्छी खबर, उठा सकेंगे पैराग्लाइंग का लुत्फ



नैनीताल, एजेंसी। जल्द सभी संचालकों को अनुमति पिल जाएगी। पैराग्लाइंग संचालन शुरू होने से पर्यटक विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी दस्तावेज तुरंत रखने वाले संचालकों को ही देहरादून निदेशालय से अनुमति दी गई।

भीमताल और नौकुचियाताल आने वाले सैलानी आज शुक्रवार से

को अनुमति पिल जाएगी। पैराग्लाइंग का लुत्फ उठ सकेंगे। पैराग्लाइंग संचालन शुरू होने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े एक हजार से अधिक स्थानीय लोगों को रोजाना मिलेगा।

जिले में भीमताल, नौकुचियाताल और कोटाबाग क्षेत्र में

के अनुसार, जल्द सभी संचालकों

संचालित की जा रही हैं। इन पर्यटक स्थलों पर दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, गुजरात, बरेली, यूपी, देहरादून, रुद्रपुर समेत अन्य शहरों के सैलानी पैराग्लाइंग का लुक उठाने पहुंचते हैं। बस्तात के बाद शुक्रवार से फिर पैराग्लाइंग का संचालन शुरू हो जाएगा।

जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़, ओपीडी 500 के पार



अल्मोड़ा, एजेंसी। मौसम में आ रहे बदलाव से अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। जिला अस्पताल में शुक्रवार को मरीजों 500 के पार पहुंची। जिला अस्पताल में सर्दी जुकाम, खुबान, एलजी, पेट दर्द, आंखों आदि रोगों के मरीज बढ़े हैं। जिला अस्पताल की ओपीडी 500 के पार पहुंची। अस्पताल में सुबह से ही रोगी पहुंचने लगे थे। फिजियोलॉग, इंफन्टी रोग विशेषज्ञ कक्ष के बाहर मरीजों की कतार रही। दूसरे दराज से भी उपचार के लिए काफी संख्या में मरीज पहुंचे थे। ओपीडी, खुन जांच, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, औषधि वितरण सभी काउंटरों पर मरीजों को अपनी बल्ली से लाने के लिए बस सेवा बढ़ाई जाएगी।

मोटा अनाज को बढ़ावा देकर उद्योग के रूप में करें स्थापित

टिहरी, एजेंसी। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित ब्लॉक स्तरीय विज्ञान सेमिनार में मोटा अनाज का अधिकारिक उद्यान कर इसके उद्योग के रूप में स्थापित करने पर जोर दिया गया। कहा कि मोटे अनाज को लेकर ऐसे विश्व में भारत की पहल पर मिलेट्रोज़ मिशन भी आयोजित किया जा रहा है। शुक्रवार को आयोजित विज्ञान सेमिनार का नाम पालिकार्यकालीन गोपनीय विक्रम सिंह प्रसाद द्वारा नेतृत्व में उद्योग करते हुए कहा गया। आयोजित विज्ञान सेमिनार की ओर से बोक्सा जनजाति की अपनी बोक्सा जनजाति को बढ़ावा देकर उद्योग के रूप में स्थापित करने की जिम्मेदारी लिया गया। अन्य विक्रम सिंह प्रसाद ने उद्योग के लिए एक छोटा अंग एक मूल्य दिया है। इसके पास एक छोटा अंग दिया है। इसके बाद उद्योग के रूप में स्थापित करने की जिम्मेदारी लिया गया।

रेलवे स्टेशन से सामान घोरी में युवक दबोचा

रुड़की, एजेंसी। रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य के दैशन लोडों का सामान घोरी करने के मायपर में पुलिस ने बाइक सवार युवक को गिरफ्तार किया है।

उससे घोरी का सामान भी बमपद कर लिया गया है। पुलिस ने केसर उद्योग को जेल भेज दिया है। अन्य दौरान देकर बताया था कि इसके बाद उद्योग के लिए देशी रोगी को देशी रोगी कर दिया जाएगा। अन्य दौरान देकर बताया था कि इसके बाद उद्योग के लिए देशी रोगी को देशी रोगी कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट-2023 का लोगो और वेबसाइट को किया लॉन्च

देहरादून, एजेंसी। मुख्यमंत्री पृष्ठ सिंह धामी ने कहा कि इंवेस्टर्स समिट पूरे राज्य और सभी विभाग के लिए महत्वपूर्ण है।

यह एक बड़ा अवसर है। कहा कि उत्तराखण्ड में निवेश को लेकर उद्योग द्वारा कहा गया। अस्त्रकारी ने किया गया।

मुख्यमंत्री पृष्ठ सिंह धामी ने

राज्य में दिसंबर में प्रसातित कर दिया गया।

यह एक बड़ा अवसर है।

संसद का मास्टर एट्रोक सत्र

संसद का मानसून सत्र 11 अगस्त को ही स्थगित किया गया था। उसके 38 दिन बाद ही मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है, तो यह मास्टर स्ट्रोक साधित हो सकता है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने 18-22 सितंबर के 5 दिनों में संसद के विशेष सत्र की घोषणा की है, लेकिन ऐजेंडे का खुलासा नहीं किया है। यह असामान्य कार्यशैली है, क्योंकि स्पीकर के साथ कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान सरकार को संसद सत्र के ऐजेंडे का खुलासा करना होता है। यही प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक सोच है। विशेष सत्र 17वीं लोकसभा का निर्णयक, अंतिम सत्र भी हो सकता है। इसके महेन्जर, यदि हाँएक देश, एक चुनाव का बिल पारित भी किया जाता है, तो वह एकदम पूरे देश पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव बीते कुछ माह के दौरान ही हुए हैं। अथवा उन्होंने अपने कार्यकाल का प्रथम वर्ष ही पूरा किया है। क्या संसद से विधानसभाओं की अवधि बढ़ाने या घटाने का संवेदनिक संशोधन प्रस्ताव भी पारित कराया जा सकता है? हालांकि चचार्द हैं कि सरकार महिला आरक्षण, समान नागरिक सहिता, एक देश एक चुनाव, आरक्षण के प्रावधान की ओबीसी की केंद्रीय सूची आदि पर नए विधेयक पेश और पारित करा सकती है। लोकसभा में महिलाओं के लिए 180 सीटें आरक्षित या बढ़ाई जा सकती हैं। मोदी सरकार ऐसा महिला आरक्षण तय करना चाहती है। अधिकतर प्रस्तावित बिलों के महेन्जर संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे, जिनके लिए कमोबेश दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत अनिवार्य होगा। संविधान संशोधन के कुछ और प्रस्ताव भी संभव हैं। चंद्रयान-3 भारत की बहुत बड़ी अंतरिक्ष और वैज्ञानिक उपलब्धि है।

एक प्रस्ताव ला सकती है। भारत को 76 साल को स्वतंत्रता के दरान जी-20 देशों की अध्यक्षता करना और शिखर सम्मेलन आयोजित करना भी अभूतपूर्व उपलब्ध है। संसद उस पर भी तालियां बजा कर प्रस्ताव पारित कर सकती है। यदि मोदी सरकार द्वाएक देश, एक चुनावहूँ का विद्येयक पेश करती है, तो यह व्यापक राजनीतिक उठल-पुथल का निर्णय होगा। देश की राजनीति ही बदल सकती है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन तो फिलहाल शैशव-काल में है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ-साथ कराना कोई नई व्यवस्था नहीं है। 1950 में संविधान लागू हुआ और 1952 में प्रथम चुनाव कराए गए। 1952, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा चुनाव भी कराए जाते रहे। चूंकि 1968 में विधानसभा-समय-पूर्व भांग की जाने लगी और 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के कारण लोकसभा चुनाव तय समय से पहले कराए गए, तो जितन व्यवस्था असंतुलित होती गई। हालांकि ऑडियो में आज भी दोनों चुनाव साथ-साथ और सफलता से कराए जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2018-19 से अपने इस मिशन की चर्चा संसद में करते रहे हैं। नीतीश कुमार और अखिलेश यादव सरीखे विपक्षी नेताओं की इस मुद्दे पर सहमति भी रही है। अब विक्ष कैसे प्रतिक्रिया देगा, यह सामने आ जाएगा, लेकिन क्या चुनाव आयोग, राज्यों के मुख्यमंत्री और सदन, अंततः सर्वोच्च अदालत अदि कई हितधारक और हिस्सेदारों से परामर्श किया गया है? क्या उनकी सहमति अनिवार्य नहीं है? दूसरे भारत और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अभी एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने वैश्विक सर्वेक्षण किया है, जिसका निर्कर्ष है कि करीब 79 फीसदी लोग और नेता भारतीय प्रधानमंत्री को पसंद करते हैं। भाजपा इस लोकप्रियता का चुनावी लाभ लेना चाहती है। उसका आकलन है कि यदि साथ-साथ चुनाव होते हैं, तो राज्यों में भी भाजपा को लाभ मिल सकता है।

अदालता फसल

द्र योगी

तुष्टिकरण जै
ते दर्शकोर्ता

किसी अन्य राज्यों की सरकारों ने शायद ही कभी खाई हो। आश्र्य की बात यह है कि अदालतों से मिली मुकदमों में हार और फटकार के बावजूद ममता सरकार ने कोई सबक नहीं रखी। ममता सरकार का रवैया सर्वधान के कायदे-कानूनों का उल्लंघन करना रहा है जिसकी दलों ने ममता सरकार की इस प्रवृत्ति पर कभी पुरोजा तरीके से विरोध नहीं किया। सत्ता में होने का बेजा फायदा उठाने की लगातार बढ़ती पुनरावृत्ति पर अदालतों ने अकुश लगाया है। ममता सरकार का रवैया ऐसा रहा है जैसे पश्चिमी बंगाल भारत के सर्वधानिक दायरे से अलग कोई देश हो। नगा मामला पश्चिम बंगाल में स्थानीय निकायों में भर्ती घोटाले से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल सरकार को अन्य मामलों को तरह इसमें भी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में स्थानीय निकाय मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि स्थानीय निकाय भर्ती और शिक्षक भर्ती घोटाले में लिंक है। इन दोनों मामले में वो सीधीआई और ईडी जांच का सामना कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवार्ड चंद्रचूड़ की अगुआई वाली तीन जजों की पीठ ने कथित घोटाले में सीधीआई और ईडी जांच को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार का अर्जी पर राहत देने से इनकार कर दिया। सीजेओआई डीवार्ड चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्टीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ ने इस दलील को मान लिया कि ये सब बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। सीधीआई जांच काफी आगे पहुंच गई है। अब इसमें दखल देते हुए रोकना उचित नहीं है। इससे पहले भी ममता सरकार को ब्रिटानर सहित कई दूसरे महत्वपूर्ण मामलों में सुप्रीम कोर्ट से हार का सामना करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट से मिली लताड़ और हार के बावजूद ममता सरकार के रवैये में कोई विशेष सुधार नहीं आया। सरकार की न तो कार्यशैली बदली और न ही तृणमूल कांग्रेस में कोई तबदीली नजर आई। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की बिना यूपीएससी के दखल के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति की अनुमति देने की याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी के मामले में कहा था कि हमारे पिछले आदेश में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने बार-बार एक ही तरह की याचिका दाखिल करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा था कि इस तरह के आवेदन कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। सुप्रीम कोर्ट एक पुराने आदेश में कह चुका है कि हर राज्य को डीजीपी की नियुक्ति से पहले यूपीएससी से योग्य अधिकारियों की लिस्ट लेनी होगी। उसी लिस्ट में से चयन करना होगा। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना था कि हर व्यवस्था गलत है।

राज्य सरकार का चयन का पूण आधिकार मेलना चाहए। सुप्रीम कोर्ट की इस व्यवस्था को लेकर भाजपा और अन्य विपक्षी दलों की राज्यों सरकारों ने कोई आपत्ति नहीं जताई। इन मामलों की तरह ही इस साल पश्चिम बंगाल में रामनवमी शोभायात्रा के दौरान हुई हिंसा मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के अदेश को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को जांच सौंपेंगे का अदेश दिया था। कलकत्ता हाई कोर्ट के इस अदेश के खिलाफ राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाह चंद्रचूड और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा ने साफ कहा कि हम विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने से इच्छुक नहीं हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने एनआईए को जांच द्वासफर करने के हाई कोर्ट के आदेश की आलोचना करते हुए कहा था कि किसी भी विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं किया गया था और यह निर्देश राजनीतिक रूप से पारित किया गया था। राज्य विधायिका में विपक्ष के नेता सुरेण्टु अधिकारी की तरफ से याचिका डाली गई थी। 27 अप्रैल को हाई कोर्ट ने रामनवमी समारोह के द्वारान और उसके बाद हावड़ा के शिवायुर और हुगली जिलों के रिशरा में हिंसा की घटाईओं की एनआईए से जांच कराने का अदेश दिया था। ममता सरकार को कानून को चुनौती देने के साथ भ्रष्टाचार जैसे मामलों में कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकी। ऐसे ही एक मामले में सरकार ने कोर्ट का रुख किया, किन्तु शीर्ष अदालत में जाना सरकार के काम नहीं आ सका। तुरंगमूल कांग्रेस नेता अधिषंक बनजी को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के बंगाल सिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवत्तन निर्देशालय की जाच को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालय के अदेश के खिलाफ अधिषंक बनजी की अपील पर सुनवाई में दिया, जिसमें हाईकोर्ट के ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो को कठित घोटाले में उनसे पूछताछ करने की अनुमति देने को चुनौती दी गई थी। ममता बनजी सरकार पश्चिम बंगाल को कैसे देश के बाहर का हिस्सा समझती है, इसका

जंगलों में आग की घटनाएँ: भारत की अध्यक्षता में जी-20 के माध्यम से प्रत्युत्तर की तैयारी

इन घटनाओं से कानून के बाहरील जगला और ब्राज़िल के अमेज़ान के विश्वविद्यालय के एक नए अध्ययन में पाया गया कि जंगलों में आग लगने की घटनाओं के कारण अब 2001 की तुलना में, प्रति वर्ष 3 मिलियन हेक्टेयर अधिक वृक्षों को नुकसान हो रहा है, जो पिछले 20 वर्षों में सभी वृक्षों के नुकसान की तुलना में एक-चौथाई से अधिक है। आग की घटनाओं की पुनर्वापत्ति, तीव्रता और भौगोलिक प्रसार में इस खटरनाक वृद्धि ने पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव और मानव गतिविधियों की क्षमता के बारे में चिंताओं को जन्म दिया है। जलवायु परिवर्तन के कारण आग की घटनाओं में वृद्धि हुई है। 150 साल पहले की तुलना में गर्म हवाओं (हीट वेव) की तीव्रता पांच गुना अधिक हो गई है। इस प्रकार भूसंरचना का निर्जलीकरण होने से जंगलों में आग लगने की और भी अधिक घटनाओं के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होता है। इसके परिणामस्वरूप उत्तर्जन में वृद्धि होती है और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तेज होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण भूसंरचना का निर्जलीकरण भी वनों की कटाई में योगदान देता है।



डॉ. क. रावचंद्रन,
निदेशक, आईआईएफएम

10

लगन का घटनाओं में काफी तजा आई है। इन घटनाओं से कनाडा के बोरियल जंगलों और ब्राजील के अमेजन के वर्षा वनों जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक कार्बन सिंक क्षेत्रों को अत्यधिक नुकसान हुआ है। मालीलैंड विश्वविद्यालय के एक नए अध्ययन में पाया गया कि जंगलों में आग लगने की घटनाओं के कारण अब 2001 की तुलना में, प्रति वर्ष 3 मिलियन हेक्टेयर अधिक वृक्षों को नुकसान हो रहा है, जो पिछले 20 वर्षों में सभी वृक्षों के नुकसान की तुलना में एक-चार्थाई से अधिक है। आग की घटनाओं की पुनरावृति, तीव्रता और भौगोलिक प्रसार में इस खतरनाक वृद्धि ने परिस्थिति तंत्र पर प्रभाव और मानव गतिविधियों की क्षमता के बारे में चिंताओं को जन्म दिया है।

जलवायु परिवर्तन के अग्रणी आग की घटनाओं में वृद्धि हुई है। 150 साल पहले की तुलना में गर्म हवाओं ($^{+1.5^{\circ}C}$) से ठंडी हवाओं ($^{-1.5^{\circ}C}$)

उत्सर्जन में वृद्धि होता है और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तेज होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण भूसंरचना का निझलीकरण भी वनों की कटाई में योगदान देता है।

भारत की स्थिति

भारत ने अपने क्षेत्र के जंगलों में आग लगने की घटनाओं को लेकर निगरानी प्रणालियों का विस्तार करके विश्व भर में जंगलों में आगजनी के बढ़ते मामलों की रोकथाम की दिशा में पहल की है। भारत के 25 प्रतिशत जंगल आग के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं, लेकिन केवल 3 प्रतिशत वृक्ष आवरण का नुकसान जंगल की आग के कारण होता है। भारतीय वन सर्वेक्षण ने आगजनी की बड़ी घटनाओं की तत्काल एवं निरंतर निगरानी और ट्रैकिंग के लिए जंगल की आग से संबंधित डेटा को उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरिक्टिव दृश्य प्रदान करने के लिए वन अग्नि जियो-र्मेंट के लिए वन अग्नि जियो-

दायर में हांगा, जिससे जंगल का आग का प्रभावी तौर पर तत्काल प्रबंधन सुनिश्चित हो सकेगा।

अधिकारियों की ओर से तकनीकी और नियामक उन्नयन के अलावा जंगल की आग की प्रबंधन रणनीति को प्रभावी ढंग से सुधारने के लिए सामूहिक कार्रवाई के उपायों को अपनाया जा रहा है। संयुक्त वन प्रबंधन (जेएफएम) का उपयोग जंगल की आग की रोकथाम और प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए किया गया है। सुरक्षा और संरक्षण को लेकर गतिविधियों के विस्तार के लिए देश भर में ग्रामीण स्तर पर जेएफएम समितियां स्थापित की गई हैं। वर्तमान में पूरे देश में 36,165 जेएफएम समितियां हैं, जो 10.24 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करती हैं।

कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले सहित भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले सहित भारत के विभिन्न क्षेत्रों में

के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी और क्षमता निर्माण शामिल है। वन विभाग ने एक वर्ष के भीतर अलर्ट में 5 प्रतिशत से अधिक की कमी का अनुभव किया गया, और जंगल की आग से जले हुए क्षेत्र में 58 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में, जंगल की आग से प्रभावित क्षेत्रों के पुनरुद्धार संबंधी कार्य को अच्छी तरह से प्रबंधित किया गया है। जिसमें घटिया स्तर का वृक्षारोपण को हटाने की कार्य प्रणालियों को मिली द्वारा सुरक्षित करना और वृक्षारोपण प्रजातियों और वयस्क पेड़ों की कुशल बंडलिंग शामिल है। इससे 12-18 महीनों के भीतर जैव विविधत के घनत्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों और मौसमी घटनाओं को देखते हुए जंगल की आग के प्रबंधन से निपटने की तैयारी कर रहा है। भारत के पारंपरिक जंगल की आग

उत्सर्जन में हांगा, जिससे जंगल का आग का प्रभावी तौर पर तत्काल प्रबंधन सुनिश्चित हो सकेगा।

अधिकारियों की ओर से तकनीकी और नियामक उन्नयन के अलावा जंगल की आग की प्रबंधन रणनीति को प्रभावी ढंग से सुधारने के लिए सामूहिक कार्रवाई के उपायों को अपनाया जा रहा है। संयुक्त वन प्रबंधन (जेएफएम) का उपयोग जंगल की आग की रोकथाम और प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए किया गया है। सुरक्षा और संरक्षण को लेकर गतिविधियों के विस्तार के लिए देश भर में ग्रामीण स्तर पर जेएफएम समितियां स्थापित की गई हैं। वर्तमान में पूरे देश में 36,165 जेएफएम समितियां हैं, जो 10.24 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करती हैं।

कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले सहित भारत के विभिन्न क्षेत्रों में

के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी और क्षमता निर्माण शामिल है। वन विभाग ने एक वर्ष के भीतर अलर्ट में 5 प्रतिशत से अधिक की कमी का अनुभव किया गया, और जंगल की आग के प्रबंधन को प्रोत्साहित करता है। साथ ही, निवारक कार्रवाई और आग की घटनाओं के बाद प्रबंधन संबंधी निर्णय लेने में फॉल्ड प्रबंधकों की सहायता के लिए आधुनिक तकनीक, जैसे अग्नि चतावनी प्रणाली, जीपीएस ट्रैक द्वारा वन अग्नि के प्रबंधन और पुनरुद्धार आदि को शामिल किया जा रहा है, ताकि आग की घटनाओं और उनसे होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।

जी20 का महत्व

जलवायु परिवर्तन पर जंगल की आग के प्रभाव के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए, इस वर्ष जी20 शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता ने जी20 वैश्वक भूमि

इकासस्टम के पुनरुद्धार संबंधी कार्य में तेजी लाने के लिए भागीदार देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा दी है।

यह जी-20 की भारत की अध्यक्षता द्वारा शुरू किया गया एक अनूठा प्रयास है। जी-20 सदस्यों की एक सहज समझ है कि जलवायु संकट को हल करने के लिए पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर सामूहिक कार्रवाई के प्रयास करने होंगे और यथासंभव परिवर्तन को एक संभावना बनाने के लिए वैश्वक परिवर्श्य में प्रभावी प्रकृति यह है कि यह रणनीतिक रूप से सामुदायिक भागीदारी और स्वदेशी ज्ञान सञ्चारण और तकनीकों के साथ स्थायी वानिकी से संबंधित कार्य प्रणालियों के सक्रिय कार्यान्वयन पर ध्यान देगी। इससे न केवल विभिन्न देशों के बीच विद्वान् आधारित सहकारी संबंधों को मजबूत करने में

एक देश एक चुनाव विचार का विद्योध करने की बजाय इससे देश को होने वाले लाभ को देखें

अब जबकि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक देश एक चुनाव पर विचार हेतु केंद्र सरकार ने एक समिति बना दी गई है, तब यह मुद्दा बहुत विचारणीय हो गया है। स्वस्थ, टिकाऊ और विकसित लोकतंत्र वही होता है, जिसमें विविधता के लिए भरपूर जगह होती है, लेकिन विरोधाभास नहीं होते। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भविष्यो-मुख्यी दृष्टिवाले नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत धीरे-धीरे इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक देश-एक टैक्स की सफलता ने इस बात को सही साखित किया है। अब तक देश के लगभग एक तिहाई राज्यों में लाग हो चुके एक नेशन-एक राशन कार्यक्रम के ऐसे ही सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। इसी



લાખપક દ્વારા પણા

ह। ये कायकाल, किसा भा महान हो सकता है। जब किसी निर्वा-

1

पड़ने वाला बोझ कम होगा, जिससे वे कंद्रमें एक निर्धारित अवधि के अंदर जब 1968-69 में अलग-अलग अपनी 170वीं सिर्पोड में लोकसभा और चुनावी खर्च के बोझ को कम से कम रुपए प्रति विधानसभा सीट बैठैत चुनावी गतिविधियों से बचा समय दृसे नए चुनाव कराना आवश्यक होता है। कारणों से कछराजों की विधानसभाएं विधानसभाओं के चानाओं को एक साथ मान लैजिए कि एक लोकसभा किया जाए जो पिछले कछराजों के

उपयोगी कामों को दे सकते हैं। अब जबकि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक देश एक चुनाव पर विचार हेतु केंद्र सरकार ने एक समिति बना दी गई है, तब यह मुद्दा बहुत विचारणीय हो गया है। स्वस्थ, चुनावों की प्रक्रिया को निर्बाध व निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न करने के लिए, ताकि वहाँ नई सरकार गठित की जा सके और देश और उस प्रदेश का काम फिर से सुचारू ढंग से चलना सुनिश्चित किया जा सके।

चुनावों की प्रक्रिया को निर्बाध व निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न करने के लिए, उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले ही भंग कर दी गईं, तो यह सिलसिला बाधित हो गया। यहाँ तक कि पहली बार लोकसभा चुनाव भी समय से पहले ही करवा लिए गए। चौथी लोकसभा का कार्यकाल 1972 तक करने का समर्थन किया था। रिपोर्ट का एक पूरा अध्याय इसी मुद्दे पर केंद्रित है। चुनाव सुधारों पर विधि आयोग की इस रिपोर्ट को देश में राजनीतिक प्रणाली के कामकाज पर अब तक के सबसे सटीक दस्तावेजों में से एक माना जाता है। इसके अन्तर्गत आने वाली आठ अलावा थोड़े-थोड़े अंतराल के बाद होने वाले चुनावों के दौरान आचार संहिता लागू हो जाने से बहुत सारे यह खर्च दोगुना हो जाएगा। लेकिन, अगर हम इन्हीं चुनावों को एक साथ करायें तो इस खर्च को काफी हड्डी

टिकाऊ और विकसित लोकांत्र वही होता है, जिसमें विविधता के लिए भरपूर जगह होती है, लेकिन विरोधाभास नहीं होते। माननीय प्रधानमंत्री ने दो बड़े मोदी के भविष्योंमुखी दृष्टि वाले नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़ा लोकांत्र भारत धीरे-धीरे इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक देश-एक टैक्स की सफलता ने इस बात को सही साबित किया है। अब तक देश के लगभग एक तिहाई राज्यों में लागू हो चुके एक नेशन-एक राशन कार्यक्रम के एसे ही सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। इसी प्रकार, एक देश-एक कानून (यूनिफॉर्म सिविल कोड) लागू किए जाने के विचार को भी जनता के एक विशाल वर्ग का अपार समर्थन मिल रहा है। एक देश-एक चुनाव लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाने का एक नीतिगत उपक्रम है। इसे समझने के लिए हमें चुनाव की प्रक्रिया को समझना होगा। हमारे देश में केंद्र और सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर, जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें कार्य करती हैं। इनका कार्यकाल पांच वर्ष का होता

काफी बड़े तंत्र व खर्च की आवश्यकता होती है। जिनमें ज्यादा चुनाव, उतनी ही ज्यादा व्यवस्था। 2023 को ही लें। इस साल राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, जम्मू-ज्ञानपूर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम समेत देश के दस राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं (इनमें से कुछ राज्यों में इस साल चुनाव हो चुके हैं)। इनमें कितने समय, धन और व्यवस्था की जरूरत पड़े गी, इसका अंदाज लगाना कोई मुश्किल कम नहीं है। ऊपर से, इन चुनावों के खत्म होते होते लोकसभा चुनावों की गहमागही शुरू हो जाएगी। अब सोचिए कि अगर इन राज्यों के और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था को जा सके तो कितना देश का कितना समय और धन बचेगा।

आज अगर हम देश के राजनीतिक परिवह्य पर न जर डालें, तो पायेंगे कि हर वर्ष देश को कोई न कोई हिस्सा चुनावमय बना रहता है। लेकिन, शुरूआत में ऐसा नहीं था। देश के पहले आम चुनावों से लेकर अगले पंद्रह सालों तक, 1952, 1957,

था, लेकिन आम चुनाव इसके पूरा होने से पहले ही 1971 में करा लिए गए। इससे समझा जा सकता है कि अगर राज्यों के विधानसभा चुनाव और आम चुनाव एक साथ आयोजित कराने की बात की जा रही है तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, जिस पर आपत्ति की जानी चाहिए। लेकिन, जब भी केंद्र में सत्तासीन एनडीए सरकार, एक बार फिर इस व्यवस्था की बहाली की बात करती है तो विपक्ष इस तरह मुखर हो उठता है कि जैसे उसे किसी भी हाल में यह नहीं होने देना है। भाजपा विरोधी कुछ दल इसे भाजपा का सत्ता का केंद्रीकरण करने की योजना कहकर इसका विरोध जारी रखे हैं, जबकि सच तो यह है कि एक देश, एक चुनाव की अवधारणा काफी पुरानी है। इस विषय पर संविधान समीक्षा आयोग, विधि आयोग, चुनाव अयोग और नीति आयोग जैसे प्रभावशाली संस्थानों की राय भी काफी सकारात्मक है। अब प्रधानमंत्री ने दो बड़ी के मजबूत नेतृत्व में राजग सरकार, राष्ट्रियत में इस विचार को और अधिक लटकाए। न रखकर एक ठोस व साकार रूप देना

जाता है। मजबूत केंद्र एवं शक्तिशाली नेतृत्व के प्रबल पक्षधर, तत्कालीन गृहमंत्री और उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने इसे राजनीतिक स्तर पर प्रमुखता से उठाया था। वर्ष 2003 में, अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था।

एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर भाजपा की इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धता, पार्टी के 2014 और 2019 के घोषणापत्रों में भी देखी जा सकती है। दूसरी बार सत्ता संभालने के महज एक ही महीने बाद, प्रधानमंत्री ने दो बड़ी मोदी ने 19 जून 2019 को इस पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसके लिए आमतिर 40 दलों में से 21 दलों के नेता इस विषय में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में रखी गई इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया, जिससे इस मुद्दे पर आम सहमति बनाई जा सके और इसके काम करने के तरीकों की व्यवहारिकता और संभावनाओं को

सेकेगा। अगर हम खर्च की ही बात करें तो पिछले पैटन को देखते हुए हम पाएंगे कि पहले आम चुनावों से लेकर पिछले आम चुनावों तक उम्मीदवारों की संख्या करीब पांच गुना बढ़ी है, लेकिन चुनावों पर आने वाला खर्च पांच हजार गुना से भी ज्यादा हो गया है। 1951-52 में जब पहले लोकसभा चुनाव हुए थे, तो इनमें 53 राजनीतिक दल चुनावी समर में उतरे थे। इन चुनावों में 1874 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और खर्च आया कुल 11 करोड़ रुपए। अब 2019 के लोकसभा चुनावों को देखते हैं। इनमें कुल 9000 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और खर्च था लगभग 60 हजार करोड़ रुपए। यानि हर लोकसभा क्षेत्र पर औसतन 110 करोड़ का खर्च। जबकि 2014 के आम चुनावों पर इसका आधा ही यानी लगभग 30 हजार करोड़ रुपए खर्च आया था।

अब देश में विधानसभा सीटों की बात करते हैं। सभी राज्यों में कुल मिलाकर विधानसभा की चार हजार से अधिक सीटें हैं। मोटे-मोटे तौर पर एक लोकसभा क्षेत्र में करीब आठ

तक कम किया जा सकता है। इससे जो धन राशि बचेगी, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने जैसे कार्यों में किया जा सकता है, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। चुनावितां भी कम नहीं सिर्फ खर्च ही नहीं, बल्कि अन्य कई दृष्टि से भी एक देश एक चुनाव का विचार काफी फायदेमंद है। इसमें प्रशासनिक तंत्र और सुरक्षा बलों पर बार-बार पड़ने वाला बोझ कम होगा, जिससे वे चुनावी गतिविधियों से बचा समय दूसरे उपयोगी कारों को दे सकते हैं। मतदाता सरकार की नीतियों को केंद्र व राज्य दोनों स्तर पर परख सकेंगे। बार-बार चुनाव होते रहने से शासन-प्रशासन के कारों में जो बाधाएं आती हैं, उनसे बचा जा सकेगा। साथ ही एक निश्चित अंतराल के बाद चुनाव कराए जाएंगे तो जनता को भी राहत मिलेगी और राजनीतिक दलों, चुनाव आयोग, चुनावों में सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियों को इनकी तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा।

બિલ્ડ એપ્પાની કાર્યક્રમ, વિધાની દૂર્જ

अंदर्जा लगाना होगा। सोशल मीडिया में जो नैरेटिव बन रहा है उसको आधार बना कर अगर विपक्षी पार्टियां कुछ भी तय करती हैं तो वह बहुत धातव हो सकता है। हालांकि विपक्ष की पार्टियों में ज्यादातर नेता मंजे हुए हैं और लंबे राजनीतिक अनुभव वाले हैं लेकिन मुश्किल यह है कि सोशल मीडिया इन दिनों हर व्यक्ति के अंदर किसी न किसी तरह का भ्रम पैदा कर देता है। सोशल मीडिया में सक्रिय हर व्यक्ति टिटहरी की तरफ उल्टा लटका दिखाता है, जो उसको पसंद आता है। इससे सत्ता विरोधी लोग घर बैठे बदलाव की आहट सुनने लगते हैं। सो, मुबई में जुट रही पार्टियों को इसका ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी भ्रम का शिकार न हों और उनकी रणनीति वास्तविक स्थितियों को ध्यान में रख कर बने। वास्तविकता यह है कि पिछले दो लोकसभा चुनावों में भाजपा का बोट बढ़ा है और पिछले करीब 10 साल में शायद ही किसी राज्य में भाजपा का बोट कम हआ है। गजयों में रणनीति बनानी होगी। भाजपा से लड़े के लिए विपक्षी पार्टियों ने मोटे तौर पर एक गठबंधन बना लिया है। इस गठबंधन की ज्यादातर पार्टियां फहले भी साथ रही हैं और कई पार्टियां अब भी साथ मिल कर चुनाव लड़ती हैं। सबकी विचारधारा एक विशिष्ट छवि गयी गई है और उसके बाद देश-विदेश की विस्तारित यात्राओं से वे इस छवि को और मजबूत कर रहे हैं। लेकिन मोटी 13 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और साडे नौ साल से प्रधानमंत्री हैं। गजयत से ही उनकी द्वितीय समाज की

विषय सोशल कीड़िया से बचे प्रिलिटी बढ़े

अजीत द्विवेदी

विपक्षी पार्टियों की तीसरी बैठक में बहुत कुछ तय होने की संभावना है। मुंबई में दो दिन की बैठक में इडियोइ की पार्टियां समन्वय समिति बनाने वाली हैं, संयोजक का नाम तय करने वाली हैं, सीट बटवरे पर चर्चा होने की संभावना है, चुनाव रणनीति बनने वाली है और लोगों व थीम सॉन्ग जारी होने की भी बता कही जा रही है। लेकिन उसमें प्रदले तथा विपक्षी कर अगर विपक्षी पार्टियां कुछ भी तय करती हैं तो वह बहुत धातक हो सकता है। हालांकि विपक्ष की पार्टियों में ज्यादातर नेता मंजे हुए हैं और लंबे राजनीतिक अनुभव वाले हैं लेकिन मुश्किल यह है कि सोशल मीडिया इन दिनों हार व्यक्ति के अंदर किसी न किसी तरह का भ्रम पैदा कर देता है। सोशल मीडिया में सक्रिय हर करते कि राहुल गांधी को सोशल मीडिया में ज्यादा पसंद किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी को कम। इसी तरह पत्रकार और विचारक श्रेणी के लोग सोशल मीडिया में पोस्ट लिख कर क्रांति करने का भ्रम पाले हुए हैं। ऐसे पत्रकारों और बुद्धिजीवियों को सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया देख कर लग रहा है कि प्रश्नांतरी नेंद्र मोदी और भाजपा की गांधी पट्टी से उत्तर गई की आहट मुनने लगते हैं। सो, मुंबई में जुट रही पार्टियों को इसका ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी भ्रम का शिकार न हों और उनकी रणनीति वास्तविक स्थितियों को ध्यान में रख कर बने। वास्तविकता यह है कि पिछले दो लोकसभा चुनावों में भाजपा का बोट बढ़ा है और पिछले कीरीब 10 साल में शायद ही किसी गज्ज में भाजपा का बोट कम हआ है। गज्जों में गठबंधन बना लिया है। इस गठबंधन की ज्यादातर पार्टियां फले भी साथ रही हैं और कई पार्टियां अब भी साथ मिल कर चुनाव लड़ती हैं। सबकी विचारधारा मोटे तौर पर एक जैसी है और राज्यों में बोट आधार भी एक जैसा है। इसलिए उसमें थोड़ी बहुत ऊंच-नीच का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद विपक्ष को केमिस्ट्री की ओर और नैरेटिव की ओर चाहिए कि उनके पास नरेंद्र मोदी से मुकाबला का कोई चेहरा नहीं है। भारत जोड़े यात्रा के जरिए राहल गांधी की एक विशिष्ट छवि गढ़ी गई है और उसके बाद देश-विदेश की विस्तारित यात्राओं से वे इस छवि को और मजबूत कर रहे हैं। लेकिन मोदी 13 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। और साथ नौ साल से प्रधानमंत्री हैं। गज्जों में गज्जात में ही उनकी द्वितीय समाचार की

ता है। रणनीति बनानी होगी। भाजपा से लड़े के तो ज्यादा फर्क नहीं पड़े वाला है। विपक्ष

दलबल व
वैर्बुई में
रखना
र न हों
थियो
वकाता
वृनुवां
फैलते
गण्ड
ज्यें में
लिए विषया पाटिया न माट तर पर एक गठबंधन बना लिया है। इस गठबंधन की ज्यादातर पार्टियां पहले भी साथ रही हैं और कई पार्टियां अब भी साथ मिल कर चूनाव लड़ती हैं। सबकी विचारधारा में तौर पर एक जैसी है और राज्यों में बोट आधार भी एक जैसा है। इसलिए उसमें थोड़ी बहुत ऊँची-नीच का ज्यादा फक्त नहीं पड़ता है। इसके बाद विषयक को केमिस्ट्री कैपेन और टैरेटिव की कंताआ जोड़े यात्रा के जरिए राह लगांधी की एक विशिष्ट छवि गही गई है और उसके बाद देश-विदेश की विस्तारण यात्रा ओंसे से वे इस छवि को और मजबूत कर रहे हैं। लेकिन मोटी 13 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और साथे नौ साल से प्रधानमंत्री हैं। यह जगत में ही उनकी छिंट बढ़त समाप्त की



मायोसाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका में हैं सामंथा

हाल ही में सामंथा ने सोशल मीडिया पर कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में समय बिताते हुए कुछ तस्वीरें शेयर की। इन दिनों सामंथा अमेरिका में मायोसाइटिस का ट्रीटमेंट ले रही है। उन्होंने वेब सीरीज सिटीडेल के इंडियन वर्जन और तेलुगु फिल्म कुशी की शूटिंग पूरी करने के बाद एक्टिंग से कुछ दिनों के लिए ब्रेक लिया है। तस्वीरें शेयर करते हुए सामंथा ने मेसिस्कन पैटर फ्रीडा काहलो की लाइन कोट करते हुए लिखा - मैं आपसे लिए खुद एक प्रेरणा हूँ। मैं खुद को सबसे अच्छी तरह से जानती हूँ और मैं खुद को और भी बेहतर तरीके से जाना चाहती हूँ। मायोसाइटिस एक ऑटो-इम्यून डिजिज है। इससे पूरे शरीर की मसलेस में सूजन बनी रहती है।



हॉलीवुड में फिर से सफलता का परचम लहराने को तैयार आदर्श गौरव

अभिनेता आदर्श गौरव किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वह मशहूर सीरीज हॉस्टल डेंज में नजर आए हैं। इसके अलावा उन्होंने द्व्यांगट टाइर में प्रियंका चोपड़ा के साथ अपना शानदार प्रदर्शन किया है। इस फिल्म ने उन्होंने अपने दमदार अभिनय के बड़े नेटवर्क लक्ज़ पर होने वाला है। नोआ हॉलीवुडीज के निदेशक और लेखक हैं, वही रिडले स्कॉट ने इसके प्रोडक्शन का काम संभाला है। बता दें कि उनके किरदार का नाम स्टाइली होगा और आदर्श इस प्रोजेक्ट से जुड़कर काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं पर्लियन की बात करें तो यह प्रतिष्ठित वेब सीरीज एलिनय फैंचाइजी की रूपांतरण है। आदर्श गौरव की बेहतरीन कलाकार हैं और उनके अभिनय ने ही उनको

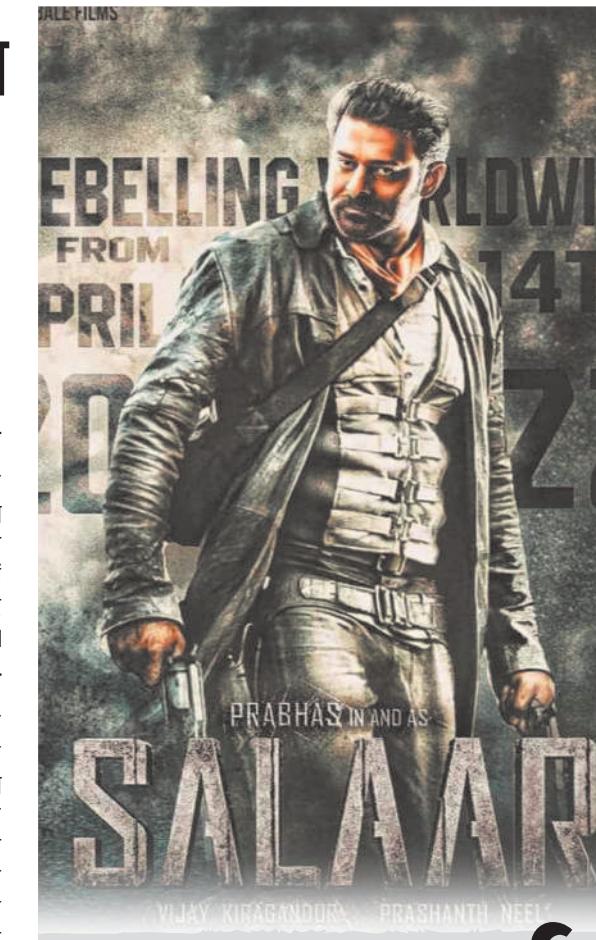
अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। द्व्यांगट टाइर में अभिनेता की हॉलीवुड फिल्म ने न केवल उनकी बेहतरीन प्रतिभा को प्रदर्शित किया, बल्कि उन्हें महान सर एंथनी हॉपकिंस के साथ प्रतिष्ठित बापटा के लिए नामांकन भी दिलाया।



तमाज़ा के बारे में पूछने जाने पर पैपराजी पर भड़के विजय वर्मा

एकटर विजय वर्मा ने हाल ही में स्ट्रीमिंग एंथोलॉजी लस्ट स्टोरीज 2 में एक्ट्रेस तमाज़ा भाटिया के साथ स्क्रीन साजा की थी। वहीं

मालदीत्य से छुट्टियां मनाकर वापस लौटे हैं। इस दौरान वह पैपराजी पर नाराज होते दिखे। एकटर मुंबई पैपरार्ट के अराइगन सेक्वेन्स से अपनी कार की ओर मुस्कराते हुए बढ़े इस दौरान फोटोग्राफरों में से एक ने उनसे पूछा, मालदीत्य से समंदर के मने लेकर आप हो? सवाल सुनते ही विजय को गुस्सा आ गया और उन्होंने जवाब में कहा - आप ऐसे सवाल नहीं कर सकते। इससे पहले तमाज़ा की एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए देखा गया था। एयरपोर्ट से एकटर की कई तर्कीरे और विडियो आशेल मीडिया पर छाए हुए हैं। 26 अगस्त को, तमाज़ा और विजय को गुब्बई पैपरार्ट पर देखा गया जब वे एक साथ छुट्टियां मनाने के लिए निकले थे। हालांकि, वह जोड़ी अला-अलग पहुँची। तमाज़ा ने अपने एक इटररूय के दौरान विजय के साथ अपने रिश्ते की पुष्टि की और उन्हें अपना हैपी लेस बताया। दूसरी तरफ, विजय ने बाद में यह भी कहा कि हालांकि वह जनता से कुछ भी छिपाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि दृश्यक उनके काम के बारे में नोटिस करें और वर्च करें, न कि उनके निजी जीवन के बारे में। वक़फ़त की बात करें तो तमाज़ा का हाल ही में रिलीज हुई क्राइम-थ्रिलर सीरीज आखिरी सर्च और रजनीकांत-स्टारर जेलर में देखा जा सकता है। विजय की एक और स्ट्रीमिंग फिल्म जाने जान रिलीज के लिए तैयार है।



पहली ब्लैकबॉल एवट्रेस हैं नीतू चंद्रा हॉलीवुड में काम करने के बावजूद फिल्म में नहीं मिलीं

2005 में रिलीज हुई फिल्म गरम मसाला से एकट्रेस नीतू चंद्रा बॉलीवुड डेब्यू किया था। हिंदी समेत तमिल, तेलुगु, कर्नाटक, ग्रीक और हॉलीवुड में भी अपनी परिटेंग की छाँ छाँड़ी। हालांकि, इसके बाद भी हक कदम पर नीतू का सधर्ष का सामना करना पड़ा। 2011 के बाद वो किसी भी हिंदी फिल्म में नहीं दिखी। काम की तलाश में कई प्रोड्यूर्स के चक्र काटे। हॉलीवुड में काम करने के बाद भी हॉलीवुड में खुद को प्रूव लगाने के लिए लड़ती रही। फिलहाल वो अपने भाई के साथ खुद के प्रूव करने के लिए गयी।

बिहार में जन्मी, स्पोर्ट्स से घ्यार मेरा जन्म पटना, बिहार के एक संयुक्त परिवार में हुआ। मैं तमाम 25-30 लोगों के बीच पटी-बड़ी हूँ। परिवार का कस्ट्रॉक्यून बिहार से आया, चाचा समेत सभी लोग ये काम करते थे। 19 बाईयों में सिर्फ 2 लड़कियां थीं लेकिन कभी किसी बीच के लिए हमें रोका नहीं गया। बचपन ही मेरा द्वाक्षाव स्पोर्ट्स की तरफ रहा। मैं तायकोड़ा में ब्लैक बेल्ट में चैपियन रही हूँ। जब मैं नौवी वकास में थी, तब हॉन्स कॉन्न, वाइना में इंडिया को रिप्रेंजेंट किया था। इसके बाद मैं लेकर पापा थोड़ा मां से नाराज होते थे। उनका मानना था कि लड़की हूँ, खेलते वक्त घोट लग गई तो आगे चलकर दिक्कत होगी। पापा की इन बातों पर मां ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। एक वही थी जिन्होंने इन चीजों के लिए मुझे हर मोड़ पर प्रोत्साहित किया। शायद यही कारण रहा कि मैं मार्शल आर्ट और स्पोर्ट्स में आगे रही। बिहार जैसे राज्य में उस समय ये सारी बीजें असामान्य थीं। बता दूँ, मैं बॉलीवुड की पहली ब्लैक बेल्ट एवट्रेस हूँ।

स्पोर्ट्स की बैदलत कॉलेज में एडमिशन मिला

परिवार में पढ़ाई को लेकर बहुत सखी थी। भले ही मैं स्पोर्ट्स में अच्छी थी लेकिन इसके साथ पढ़ाई में अच्छा होना जरूरी था। 12वीं तक की पढ़ाई में विहार के लिए दिल्ली जाना पसंद करते हैं। यहां पर जब मैं इंटर्व्यू कॉलेज गई तो उनका कहना था कि एडमिशन ने देने में नाम करना था। उनका कहना था कि 62% के साथ मेरा एडमिशन नहीं हो सकता। इसके बाद स्पोर्ट्स के स्टर्टिफिकेट दिखाया जिसके बाद स्पोर्ट्स कोटे पर मुझे एडमिशन और हॉस्टल दोनों मिल गए। कॉलेज में भी रेट्रोस्टैन, मिस फेशर और मिस हॉस्टल रही।

कैटलॉग शूट से खर्चा चलाया सबसे बड़ा सधर्ष तो पैसे को लेकर होता था। इससे मैं अच्छी नहीं रही। कुछ समय बाद सारी सेविंस खत्म हो गई। कोई बड़ा काम भी नहीं मिल रहा था, इसलिए साड़ी कैटलॉग के लिए शूट करने लगी। एक साड़ी के शूट के लिए 500 रुपए मिलते थे। पैसों की सख्त जरूरत थी तो एक दिन में मैं 15 से 20 साड़ियों के लिए शूट करती थीं। इस तरह से मैंने कुछ दिन का खर्चा निकाला।

डायरेक्टर प्रियदर्शन ने बदल दी किस्मत

एक दिन में घर में थी, तभी कॉल आया। कॉल उठाते ही सामने आया आई - मैं प्रियदर्शन बोल रहा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे कॉल करेंगे। फिर जब उन्होंने दिल्ली के लिए शूट करने लगे। तब मैं शॉवट रह गई। उन्होंने बताया कि वो फिल्म गरम मसाला बना रहे हैं जिसमें वो अक्षय कुमार और जन अब्दुल हम अपेक्षित थे। इसके बाद वो अपेक्षित थे कि वो लॉन्च कर रहे हैं। तब मैं लड़कियों में वो मुझे भी लॉन्च करना चाहते हैं। ये मूँह में फैले नहीं सामाइ और जान से फिल्म के लिए हाँ कर दिया। इस तरह से मैंने मेरा फिल्मी डेब्यू हुआ।

हॉलीवुड में एंट्री मिली, वीजा पाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया

मैंने ब्लैक बेल्ट हूँ और इसी हुएर ने मुझे हॉलीवुड फिल्म नेवर बैक डाइन-रिपोर्ट दिलवाई। फिर एक नई मुर्बीवाल सामने आ गई। काम मिला लेकिन शूटिंग के लिए लंदन जाने के लिए वीजा ही नहीं मिल रहा था। इसके लिए मैं पहले मुर्बी ऐब्रेसी गई, लेकिन वहां बात नहीं बढ़ी थी। वीजा नहीं मिल रहा था। इसके बाद मैं एंट्री करने के लिए लड़कियों में वो मुझे भी लॉन्च करना चाहते हैं। ये मूँह में फैले नहीं सामाइ और जान से फिल्म के लिए हाँ कर दिया। इस तरह से मैंने मेरा फिल्मी डेब्यू हुआ।

सालार हुई पोस्टपॉन लगी 3.30 करोड़ की चपत

शाहरुख खान की जवान के भौकाल के बीच प्रभास की सालार की पोस्टपॉन की खबर सामने आ गई। काम मिला लेकिन शूटिंग के लिए लंदन जाने के लिए वीजा ही नहीं मिल रहा था। इसके लिए मैं पहले मुर्बी ऐब्रेसी गई, लेकिन वहां बात नहीं बढ़ी थी। वीजा नहीं मिल रहा था। इसके बाद मैं एंट्री करने के लिए लड़कियों में वो मुझे भी लॉन्च करने की चेतावनी आई। वीजा नहीं मिल रहा था। इसके बाद मैं एंट्री करने के लिए लड़कियों में वो मुझे भी लॉन्च करने की चेतावनी आई। वीजा नहीं मिल रहा था। इसके बाद मैं एंट्री करने के लिए लड़कियों में वो मुझे भी लॉन्च करने की चेतावनी आई। वीजा नहीं मिल रहा था। इसके बाद मैं एंट्री करने के लिए लड़कियों में वो मुझे भी लॉन्च करने की चेतावनी आई। वीजा नहीं मिल रहा था। इसके बाद मैं एंट्री करने के लिए लड़कियों में

